

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



लद्दाख का राजपत्र The Ladakh Gazette

एस.जी.-एल.डी.-अ.-01122023-1272
SG-LD-E-01122023-1272

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

लद्दाख, 01 दिसंबर, 2023
LADAKH, FRIDAY, DECEMBER, 01, 2023

भाग I
Part I

केन्द्र-शासित प्रदेश लद्दाख प्रशासन
ADMINISTRATION OF UNION TERRITORY OF LADAKH

विषयः: शस्त्र अधिनियम, 1959 एवं शस्त्र नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार व्यक्तिगत शस्त्र लाइसेंस का प्रदान - संबंधित निर्देश।

आदेश संख्या: 84-गृह 2023

दिनांक: 22.11.2023

इस वषय पर और पछले सभी आदेशों के अधक्रमण में, संघ राज्य लद्दाख में नए व्यक्तिगत शस्त्र लाइसेंस जारी करने की मंजूरी दी जाती है और यह भी आदेश दिया जाता है कि जिला मजिस्ट्रेट (लाइसेंस संग्रह प्रशासन) सहित सभी संबंधित, शस्त्र अधिनियम, 1959 और शस्त्र नियम, 2016 के प्रावधानों का पालन करने के अलावा, निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों का भी पालन करेंगे:

1. जिला मजिस्ट्रेट शस्त्र नियम, 2016 के 'फॉर्म III' के तहत 'आत्म-सुरक्षा' के उद्देश्य से केवल गैर-निष्पक्ष बोर आग्नेयास्त्रों के लिए शस्त्र लाइसेंस जारी करेंगे या पुराने शस्त्र लाइसेंस का नवीनीकरण करेंगे। इसके लिए, जिला मजिस्ट्रेट शपथ पत्र के रूप में आवेदक से एक एफडे वट लेंगे कि 'लाइसेंस प्राप्त हथियार का उपयोग वन्यजीवों (जंगली जानवरों और पक्षियों) के शिकार के लिए नहीं किया जाएगा'।
2. 'खेल' श्रेणी के लिए शस्त्र लाइसेंस गृह विभाग द्वारा नियमों के तहत वास्तविक आवेदकों को जारी किए जाएंगे।
3. जिला मजिस्ट्रेट द्वारा, व्यक्तिगत शस्त्र लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन पर विचार करते समय, पहचान-पत्र के रूप में आधार कार्ड अनिवार्य रूप से लिया जाएगा।
4. जिला मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करेंगे कि वे केवल अपने जिले के वास्तविक निवासी और 08 अक्टूबर, 2021 के आदेश, 2022 के तहत जारी यूटी लद्दाख निवासी प्रमाण पत्र रखने वाले लोगों को ही लाइसेंस दें या लाइसेंस का नवीनीकरण करें।
5. लद्दाख में सेवारत रक्षा/अर्धसैनिक कर्मियों के मामले में, निवासी मानदंड सुनिश्चित करने के लिए यूनिट के कमांडिंग ऑफसर द्वारा जारी सेवा प्रमाणपत्र अनिवार्य होगा। इसके अलावा, किसी भी आवेदन पर कार्रवाई करने से पहले जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा पुलिस से एक वरिष्ठ रिपोर्ट प्राप्त की जाएगी, जिसे प्रमाणित किया जाएगा। और किसी भी सूरत में, जिला मजिस्ट्रेट लाइसेंसधारक के पते से संबंधित शस्त्र नियम, 2016 के नियम 17 और नियम 24 से वंचित नहीं होंगे।
6. पस्तौल और रिवॉल्वर जैसे छोटे हथियारों के लिए लाइसेंस जारी करने से पहले, जिला मजिस्ट्रेट ऐसे मामलों में हथियार खरीदने की आवश्यकता को सुनिश्चित करते हुए एसएसपी सीआईडी से एक सीआईडी रिपोर्ट प्राप्त करेंगे। अन्य मामलों (जैसे एसबीबीएल/डीबीबीएल लाइसेंस) में जिला मजिस्ट्रेट शस्त्र नियम, 2016 के तहत निर्धारित, आवेदक के चरित्र और पूर्ववृत्त के संबंध में निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी से एक रिपोर्ट प्राप्त करेंगे, ताकि सामाजिक और सार्वजनिक जीवन के संबंध में प्रत्येक व्यक्ति के आचरण और लाइसेंस प्रदान की योग्यता को सार्थक बनाया जा सके, साथ ही आंतरिक सुरक्षा पर भी विचार किया जा सके।
7. जिला मजिस्ट्रेट व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करेंगे कि शस्त्र नियमों के तहत प्रदान की जाने वाली प्रत्येक सेवा, जिसमें लाइसेंस प्रदान करना, लाइसेंस का नवीकरण, क्षेत्र वैधता का विस्तार, हथियार गोला-बारूद की प्रविष्टि, लाइसेंसधारक के

- निवास परिवर्तन के मामले में पंजीकरण आदि अनिवार्य रूप से एनडीएएल/एएलआईएस पोर्टल के माध्यम से कए जाएं और उक्त पोर्टल पर की गई ऐसी सभी प्र वष्टियों का भौतिक रिकॉर्ड (व धवत अ धप्रमाणत) उनके कार्यालयों में समवर्ती रूप से रखा जाएगा।
8. तदनुसार, जारी करने, नवीकरण या कसी अन्य ह थयार संबंधी सेवाओं के लए सभी आवेदन जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा केवल ऑन-लाइन मोड अर्थात लाइसेंस संग पोर्टल एनडीएएल-एएलआईएस के माध्यम से प्राप्त कए जाएंगे।
 9. जिला मजिस्ट्रेट व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करेंगे क एनडीएएल-एएलआईएस पोर्टल पर अपलोड कए गए कसी भी संभावत लाइसेंसधारक या शस्त्र नियमों के तहत कसी भी सेवा का उपयोग करने वाले लाइसेंसधारक का डेटा/ ववरण सही और त्रुटि रहित हो ।
 10. जिला मजिस्ट्रेट, जिला पुलिस अधीक्षकों के समन्वय से, अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर सभी लाइसेंसधारकों पर नज़र रखेंगे और वे यह सुनिश्चित करेंगे क लाइसेंसधारकों द्वारा लाइसेंस की क्षेत्र वैधता का पालन कया जाए।
 11. शस्त्र नियमों के अंतर्गत जारी करने/नवीकरण या कसी अन्य संबद्ध सेवाओं के अधिकार मजिस्ट्रेट द्वारा लाइसेंस संग प्राधिकारी से कम कसी भी अधिकारी को नहीं दिया जाएगा, जो शस्त्र अधिनियम 1959 और शस्त्र नियम 2016 का उल्लंघन करता हो।

संघ राज्य लद्दाख के उपराज्यपाल के आदेश से जारी

HOME DEPARTMENT

UT Secretariat

Subject: Issuance of individual Arms Licenses in terms of the Arms Act, 1959 and Arms Rules, 2016 -Instructions reg.

Order No. 84-Home of 2023

Dated : 22.11.2023

In supersession of all previous orders on the subject, sanction is hereby accorded for issuing fresh individual Arms Licenses in the Union Territory of Ladakh. It is further ordered that all the concerned including District Magistrates (Licensing Authorities), besides following the provision of the Arms Act, 1959 and Arms Rules, 2016, shall also adhere to the following additional conditions:

1. The District Magistrates shall issue Arms Licenses or renew old Arms Licenses for Non-Prohibited Bore Firearms only, for the purpose of 'self-protection' under 'Form-III' of the Arms Rules, 2016. For this, the District Magistrates shall take an 'undertaking' from the applicant in the shape of affidavit that 'the licensed weapon shall not be used for hunting wildlife (Wild Animals & Birds)'.
2. The Arms Licenses for the 'sport' category shall be issued by the Home Department to bona fide applicants under rules.
3. The District Magistrates, while considering an application for grant of individual Arms Licenses, shall necessarily obtain Aadhar Card as a proof of identity.
4. The District Magistrates shall ensure that they entertain applications from Civilians for grant of license or renewal of Arms Licenses only from the bona fide resident of their district who possess the Ladakh Resident Certificate issued to them under *UT Ladakh Grant of Resident Certificate (Procedure) Order, 2022 Dated 08th October, 2021*.
5. In case of Defence/Paramilitary personnel serving in Ladakh, the Serving Certificate issued by the Commanding Officer of the Unit shall be mandatory to ascertain the residence criteria. Moreover, a specific report from the Police, certifying the same, shall be obtained by the District Magistrates before processing any application. *In no case*, of that particular district and in no case the District Magistrates shall deviate from the Rules 17 & Rule 24 of Arms Rules, 2016, concerning the addresses of the licensee.
6. Before issuing the license for small arms like Pistols and Revolvers, the District Magistrates shall obtain a CID report from the SSP CID justifying the requirement of procuring the weapon in such cases. In other cases (like SBBL/DBBL licenses) the District Magistrates shall obtain a report from the Officer-in-Charge of the nearest Police Station, regarding the character and antecedents of the applicant, as prescribed under the Arms Rules, 2016, in order to ascertain the suitability of granting license in each individual with respect to his/ her conduct social and public life, as also the internal security consideration.
7. The District Magistrates shall personally ensure that every service to be provided under the Arms Rules, including grant of license, renewal of license, extension of area validity, making entry of Arms/ ammunition, registration in case of change of residence of the licensee etc. are mandatorily done through NDAL/ALIS portal and physical record (duly authenticated) of all such entries which are made on the said portal are maintained concurrently in their offices.
8. Accordingly, all the applications for issuance, renewal or any other Arms related services shall be received by the District Magistrates only through On-line mode viz. licensing portal NDAL-ALIS.

9. The District Magistrates shall personally ensure that data/detail of any prospective licensee or of a licensee who is accessing any service under Arms Rules, uploaded on NDAL-ALIS portal, is correct and error-free.
10. The District Magistrates, in coordination with the District Superintendents of Police, shall keep track of all the licensees within their jurisdiction and they shall ensure that the area validity of the license is adhered to by the licensees.
11. No delegation of powers about issuance/renewal or any other allied services under Arms Rules, shall be made by the District Magistrate to any authority subordinate to the licensing authority in violation of Arms Act 1959 and Arms Rules, 2016.

By Order of the Lieutenant Governor, UT of Ladakh.

Sd/-
(Dr. Pawan Kotwal, IAS)
Advisor/
Administrative Secretary
Home Department

No: Home/UTL/188/ALIS/2023-3695-3702

Dated:22.11.2023

(Ms. Suman Beniwal, IFS)
Additional Secretary,
Home Department.

"No legal responsibility is accepted for the contents of publication of advertisements/publications in this part of The Ladakh Gazette. Persons notifying the advertisements/public notices will remain solely responsible for the legal consequences and also for any other misrepresentation etc."